

DATE: 29/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART 2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 59 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO. - 22

By,

OM KUMAR SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

DEPTT. OF POL. SC.

D.B. COLLEGE, JAYNAGAR

LNMU, DARBHANGA

न्यायिक सक्रियतावाद का आभाव

न्यायिक सक्रियतावाद का आभाव है कि "संविधान, कानून और अपने हाथियों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक - आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन लाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना।"

न्यायिक सक्रियतावाद के अन्तर्गत यह बात सामिलित है कि जन समान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वैच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का हाथित्व है। इसके पक्षधर न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने 1982 में कहा था, "सर्वोच्च न्यायालय ने विगत दो वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है।"

1980 से न्यायिक सक्रियता में निरन्तर वृद्धि ही हुई है। मई 2010 में उच्च. उच्च. कपाड़िया के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद ग्रहण

के बाद इसमें और वृद्धि हुई। फरवरी 2012 ई. में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा दूर-संचार के क्षेत्र में दिये गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिये और सरकार को निर्देश दिया कि 'मुपजी नीमाम की प्रक्रिया' को अपनाते हुए नये लाइसेंस जारी करें।

परम्परागत रूप में यह माना जाता रहा है कि न्यायपालिका की राज व्यवस्था में मात्र निषेधात्मक भूमिका ही प्राप्त है, लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद के आधार पर, न्यायपालिका को निषेधात्मक भूमिका के साथ-साथ एक सकरात्मक भूमिका, वस्तुतः एक रचनात्मक भूमिका प्राप्त हो जाती है। इसी आधार पर कुछ विद्वान 'न्यायिक सक्रियतावाद' के स्थान पर 'न्यायिक रचनात्मकता' या 'न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका' शब्दों का प्रयोग करते हैं।

सम्भावित प्रश्न :

न्यायिक सक्रियतावाद का आशय क्या है ?

